SHRIMATI BRINDA KARAT: Relocation of the habitat has to be by an expert committee.

SHRI JAIRAM RAMESH: It is not done in an arbitrary fashion. It is done in professional, consultative manner. But, as I said, this is not the time to argue. If you have evidence to the contrary, I and my officers from the National Tiger Conservation Authority will sit with you and we will rectify matters. We want it to be a democratic and voluntary process of relocation. But we must relocate from the core areas. That is an uncompromising policy.

SHRIMATI BRINDA KARAT: It is the identification of that habitat that I am talking about. *...(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I will get back to the Member on the Sethusamudram project. On the other issue of declaring disturbed areas, giving them a 90:10 dispensation, this I am afraid, is an issue that only the Planning Commission can pronounce on. The Special Category States are entitled to 90:10; Chhattisgarh is not a Special Category State. I may inform hon. Members, Sir, that I am in the process of putting together a programme for modernisation of forest administration with particular reference to naxalite-affected States such as Jharkhand, Orissa, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and even parts of Maharashtra, particularly Gadchiroli and Chandrapur. A draft of that scheme has been prepared. I have shared it with the hon. Home Minister, and I hope that in the next few months, just like we have a scheme for modernisation of police administration, we will also have a programme for modernisation of forestry administration as an element of countering the naxalite problem in these five badly affected States.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Minister, for the elaborate reply. Now, we shall take up discussion on continued rise in prices of essential commodities in the country. Shri Shivanand Tiwari to iniate the discussion.

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Sir, I have a suggestion to make. Both these issues, that is, discussion on price rise and clarification to the statement, are similar and on the same subject; they can be taken up together. That would be better as both the matters can be disposed of together, if the hon. Minister agrees.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let hon. Members make their points and let us have the discussion.

SHORT DURATION DISCUSSION

The situation arising out of continued rise in prices of essential commodities in the country

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की शुरुआत करने का मौका दिया है। यह एक ऐसा विषय है, जोकि देश की दो-तिहाई आबादी के लिए जीवन-मरण का संकट पैदा करने वाला एक मुद्दा है।

उपसभापति महोदय, आज महँगाई की यह जो हालत है, वह अचानक सुरसा की तरह मुँह बा कर हमारे सामने प्रकट नहीं हुई है। आप देखेंगे कि सरकार ने पिछले सालों में जो आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किये हैं, वे सर्वेक्षण ही यह बता रहे हैं कि यह महँगाई आज अचानक हमारे सामने नहीं उठ खड़ी हुई है, बल्कि पिछले तीन-चार वर्षों से महँगाई हमारे देश में लगातार बढ़ रही है। सरकार ने अप्रैल 2004-2005 का जो आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पेश किया था, उसके अनुसार जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जो Consumer Price Index है, उसमें 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके बाद अप्रैल 2005-2006 में यह 5 प्रतिशत हो गई, 2006-2007 में यह 5.6 प्रतिशत हो गई, 2007-2008 में 6.67 प्रतिशत और 2008-2009 में 7.8 प्रतिशत हो गई तथा आज यह महँगाई double digit में पहुँच गई है। यह हमारा आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। लेकिन, हमें आश्चर्य है कि हमारे देश में यह सियासत का मुद्दा नहीं बना। उपसभापति महोदय, यह भी देखा जाए कि जो UPA-I थी, यानी इसके पहले वाली जो UPA की सरकार थी, उस समय भी देश के गरीबों की हालत अच्छी नहीं थी। यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सरकार के सारे आँकड़े, सरकार की सारी एजेंसी इस बात की गवाही दे रही है। जैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की यह जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है, यह National Sample Survey की है। उसके आधार पर UPA सरकार के पिछले पाँच वर्षों में गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी और बेरोज़गारी बढ़ी। National Sample Survey Institute के आँकड़ों का विश्लेषण करते हुए Indian Statistical Society ने कहा है कि देश में 32.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। पाँच वर्ष पहले जब UPA-I सत्ता में आयी थी, उस समय यह संख्या 27.5 करोड़ थी। विश्व बैंक के अनुसार गांवों में 50 परसेंट और शहरों में 38 परसेंट लोग कुपोषण के शिकार हैं। UNO के World Food Programme के अनुसार देश में 22 करोड़ लोग गरीबी और भुखमरी के शिकार हैं। ये सारे आंकड़े बता रहे थे कि UPA-I के कार्यकाल में भी जो देश का गरीब आदमी या आम आदमी है, उसकी हालत बिगड़ती गई। लेकिन, मेरे जैसे आदमी को ताज्जुब होता है कि आखिर यह सियासत का मुद्दा क्यों नहीं बना? यह राजनीति का मुद्दा क्यों नहीं बना? हमने लोक सभा का जो पिछला चुनाव लड़ा, उसमें महंगाई मुद्दा नहीं बनी, बेराजगारी मुद्दा नहीं बनी, गरीबी मुद्दा नहीं बनी, इसका क्या कारण है?

उपसभापति महोदय, आज से 39-40 साल पहले जब हमने एक कार्यकर्त्ता के रू प में राजनीति की शुरू आत की थी, उस समय नारा लगाया जाता था कि 'जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा।' भूखे इंसानों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन नारा बंद हो गया। हम लोग नारा लगाते थे कि "कमाने वाला खायेगा, लूटने वाला जाएगा।" आज कमाने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं और लूटने वाले लोग मौज कर रहे हैं, लेकिन यह राजनीति का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। आखिर क्या कारण है? महोदय, मैंने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की। मैंने हमेशा anti-establishment politics की, इसलिए सत्ता की राजनीति को मैं बहुत नहीं समझता हूँ, लेकिन मैंने यह जानने का प्रयास किया कि हमारे देश की राजनीति में गरीबी, बेरोजगारी और गैर-बराबरी का जो सवाल है, आखिर क्या कारण है कि वह मुद्दा नहीं बन पा रहा है? एक जमाना था जब निचले सदन में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधान मंत्री हुआ करते थे, हम लोगों के नेता डा. राम मनोहर लोहिया सदन में चुन कर आये थे। हमको ध्यान है कि जब लोहिया जी जीत कर लोक सभा में आये थे, तो 'The Statesman' ने लिखा था कि 'A Bull in China shop'. उस समय देश की गैर-बराबरी पर बहस हुई थी और "तीन आना बनाम तेरह आना" - देश का जो आम आदमी है, उसकी आमदनी तीन आना प्रति दिन है, इसको प्रधान मंत्री जी ने चुनौती दी थी और अंत में settle हुआ कि नहीं, आम आदमी की आमदनी तेरह आने प्रति दिन है। उस समय ये सारी चीजें राजनीति के मुद्दे बनते थे, लेकिन आज यह राजनीति का मुद्दा नहीं बन रहा है, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की राजनीति पर जन-बल से ज्यादा धन-बल का प्रभाव बढ़ा है। अभी हम देख रहे थे, श्री पी. साईनाथ जी 'The Hindu' अखबार के ग्रामीण क्षेत्र के सम्पादक हैं, वह बहुत ही संवेदनशील आदमी हैं। जो पिछला लोक सभा चुनाव हुआ, उसका उन्होंने विश्लेषण किया और विश्लेषण करके वह इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारे यहाँ जो 543 सांसद चुने गये, उनकी कुल सम्पत्ति 2,800

4.00 P.M.

करोड़ रुपये की है। उन्होंने कहा कि 10 लाख से कम आमदनी वाले जो प्रतिनिधि चुनाव में जीते हैं, उनकी तादाद 0.7 परसेंट है, जिनकी सम्पत्ति 50 लाख से 5 करोड़ रही है, वैसे 19 परसेंट लोग लोक सभा में जीत कर आये हैं और 5 करोड़ से ऊपर की सम्पत्ति वाले 33 परसेंट लोग जीते हैं। यह हालत है। सियासत में धन-बल किस तरह से बढ़ रहा है, उसका यह एक नमूना है। महोदय, यही नहीं, मेरे पिताजी ...**(व्यवधान)**... मैं कारण बता रहा हूँ। यह जो महंगाई का मामला है, यह कोई अकेला मामला नहीं है। मेरे पिताजी 1952 में एम.एल.ए. बने, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामानन्द तिवारी, तारकेश्वरी सिन्हा, केदार पांडेय, जो यहाँ रेलवे मिनिस्टर थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, सब लोग साथ रहते थे। उस समय विधायकों और सांसदों को बहुत कम सुविधाएँ मिलती थीं। लेकिन, उस समय जन-प्रतिनिधि और जनता के बीच में एक रिश्ता था। मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि जैसे-जैसे जन-प्रतिनिधियों की सुविधाएँ बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे जनता और जन-प्रतिनिधियों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, इसलिए महंगाई जैसा मुद्दा, दरिद्रता जैसा मुद्दा, बेराजगारी जैसा मुद्दा और गैर-बराबरी जैसा मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। यह मैं कहना चाहूँगा।

उपसभापति महोदय, हमारे देश की कृषि नीति में बदलाव शुरु हुआ 1968 से 1978 के बीच में, उसके पहले 1965-66 में देश में सुखाड़ पड़ा। उस समय 1967 में देश के 9 राज्यों और बिहार में भी संविद की सरकारें बनी थीं। इतना जबर्दस्त खुखाड़ था कि हम लोगों को हाथ पसारना पड़ा। PL-480 के अंतर्गत अमरीका से हम लोगों ने अनाज मंगाया था, ललका जोंगही बांटा जाता था, अभी भी पुराने लोगों को याद है और उसके बाद सरकार ने कमर कसी कि हम अन्न के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे और Green Revolution की शुरुआत हुई। इस Green Revolution ने खेती को पूरा का पूरा बदल दिया, लेकिन हम लोगों ने अपनी परम्परागत खेती का विकास नहीं किया। आयातित बीज, खाद, टैक्नोलॉजी, खेती का पूरा तरीका हम लोगों ने आयात किया और उसका नतीजा क्या निकला? Green Revolution का प्रभाव पूरे देश में नहीं पड़ा, कुछ खास ही इलाके Green Revolution का फायदा उठा सके और बाकी इलाके जस-का-तस रह गए। इसका नतीजा यह हुआ कि क्षेत्रीय गैर बराबरी बढ़ी, खेती की लागत में वृद्धि हुई, जो परम्परागत खेती थी उससे कई गुणा ज्यादा खेती की लागत में वृद्धि हुई और इसके अलावा Green Revolution में कुछ अनाजों पर ज्यादा जोर दिया गया - गेहूं, धान, maize पर। इन दो-चार अनाजों पर Green Revolution में ज्यादा जोर दिया गया और बाकी जो हमारे अनाज थे, हमारे देश में जो अन्न के प्रकार थे, जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती थी, वे सारे के सारे छूट गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज एक तो देश में गैर बराबरी बढ़ी और दूसरे जो स्थानीय फूड हेबिट में व्यापक बदलाव आया। हम लोग जिस इलाके रहने वाले हैं, उस इलाके में हम लोग चावल को *भात* कहते हैं। हमारे इलाके में हम लोग मक्का का *भात* बनाकर खाते थे, चावल के *भात* के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं थे। तो जो वेराइटी थी अनाज खाने की, उसमें कमी आई और पूरे देश में धान और गेहूं की ही खपत हो गई। लेकिन, फिर धीरे-धीरे क्या हुआ? धीरे-धीरे यह हालत हुई कि हमारे यहां आबादी के बढ़ने की रफ्तार और खेती में उत्पादकता बढ़ने की रफ्तार के बीच में गैप हुआ। आज हमारी आबादी बढ़ रही है, अभी श्री जयराम रमेश जी बोल रहे थे, डेढ़ परसैंट के हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारी खेती की प्रोडक्टिविटी एक परसैंट के हिसाब से बढ़ रही है। इस तरह से जो डिमांड और सप्लाई में mismatch हुआ, उसने भी आज के संकट को बढ़ाने में मदद की और दलहन तथा तिलहन के क्षेत्र में तो सरकार ने और इस देश के कृषि वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा अपराध किया है, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। न दलहन के मामले में कोई रिसर्च हुई, न तिलहन के मामले में कोई रिसर्च हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि दलहन थाली से गायब होने लगी। आज जो महंगाई की हालत है और दालों की कीमत है, गरीब आदमी को तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनकी थाली से भी दाल गायब हो रही है, ऐसी स्थिति हम लोगों के यहां पैदा हो गई है। Green Revolution के बाद हम लोगों ने दावा किया था कि अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया है। क्या स्थिति है? वर्ष 2000 में हम लोगों ने अन्न का आयात किया 2.6 बिलियन डॉलर का और 2007

में यह आयात 4.9 बिलियन डॉलर का हो गया, यह हालत है। 120 करोड़ की आबादी वाला देश, इतने बड़े आकार का देश, अनाज का आयात करके अपने आपको कैसे स्वायत्त बना सकता है, अपनी sovereignty को कैसे बरकरार रख सकता है, अपने आत्मस्वाभिमान को कैसे बरकरार रख सकता है? क्या हालत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2006 में आपने 5.5 मिलियन टन गेहूं आयात किया। किस भाव में आयात किया? आपने आयात किया 178.75 डॉलर से लेकर 228.94 डॉलर प्रति टन के बीच में। दो-तीन बरस पूर्व तक देश में पर्याप्त अनाज था, यहां माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, उस समय हमारे देश में 74.82 मिलियन टन का भंडार था और उस समय हम लोगों ने मिनिमम् सपोर्ट प्राइस 850 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का रखा था। इसके बावजूद हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, इतना बड़ा अन्न भंडार रहते हुए भी, 1600 रुपए टन के हिसाब से अनाज आयात किया।

उस समय बहुत शोर मचा था, बहुत अंगुली उठी थी कि इस आयात में गड़बड़ी हुई है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : तिवारी जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री शिवानन्द तिवारी : मैं समाप्त कर रहा हूं, मुझे 5 मिनट का समय और दे दीजिए ...**(व्यवधान)**... यह परंपरा रही है कि जिन लोगों ने बहस की शुरुआत की है, उनको थोड़ा समय मिलता है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे 20-25 मिनट का समय देंगे।

श्री उपसभापति : मैंने 15 मिनट का समय दिया है, इससे ज्यादा समय मैं क्या दे सकूंगा?

श्री शिवानन्द तिवारी : आज हम अनाज का आयात कर रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, हमारे देश में 40 परसेंट बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, यह हालत है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, हमारे देश में कम भार वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों में GDP growth के बारे में इस देश में जो शोर मचा, उस शोर में गरीबों की आवाज दब गई। हालत यह हुई कि एक तरफ GDP की growth हो रही है और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, कम भार वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, आधी से अधिक औरतें anaemic हैं, लेकिन शोर यह कि GDP बढ़ रही है और कोई डर के मारे इन स्थितियों के बारे में बोल नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम गरीबों की बात उठाएंगे, तो कहा जाएगा कि यह आदमी कितना पीछे देखने वाला है। इसका कारण क्या है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। जो सबसे बड़ा कारण है, वह है - खेती के उत्पादन में mismatch और दूसरा कारण यह है कि इस देश में future trading in commodities की एक नयी समस्या पैदा हुई है। वर्ष 2003-04 में सरकार ने future trading की मान्यता दे दी और उस समय माना गया था कि इससे price में stability आएगी और किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, इसी भरोसे के तहत आपने future trading यानी वादा बाजार की अनुमति दे दी। वर्ष 2005-06 से वादा बाजार में गति आई। पहले जहां जनवरी, 2005 में 58 जिंसों में वादा बाजार का कारोबार होता था, वहीं दिसंबर, 2006 में 94 जिंसों में वादा बाजार का कारोबार शुरू हुआ। 2005 और 2007 के बीच यह कारोबार 16 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए हो गया। हमारे जैसा आदमी तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता है कि 36 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं और आज 2008-09 में यह वादा बाजार 52,48,956 करोड़ रुपए का हो गया है, पिछले साल यह वादा बाजार 40,55,989 करोड़ रुपए का था। इतनी वृद्धि देखकर किसी का भी माथा चकरा जाए। यह जो amount इसमें involved है, हमारे देश का जो total agricultural produce है, जितना भी कृषि उत्पादन है, उससे 8 गुना, 9 गुना ज्यादा कीमत का वादा बाजार हमारे देश में हो रहा है। यह वादा बाजार जिन लोगों का है, उनको दामों में स्थिरता से कोई मतलब नहीं है। उनका लाभ इसी में है कि दाम अस्थिर रहें और आप देखिएगा कि 2005-06 से वादा बाजार ने इस देश में गति पकड़ी और उसी समय से इस देश में अस्थिरता का माहौल शुरू हुआ, नहीं तो हमारे देश में जो खेती का उत्पाद था, उसके दाम में स्थिरता रहा करती थी, लेकिन इस वादा बाजार ने दामों में अस्थिरता को पैदा किया। मैं यह कहूंगा कि अगर सरकार यह चाहती है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: तिवारी जी, अब आप समाप्त कीजिए। कुल 24 मेंबर्स बोलने वाले हैं, आपने शुरू किया है।

श्री शिवानन्द तिवारी: उपसभापति जी, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि दामों को आप रोकना चाहते हैं, अगर आप प्राईस पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वादा बाजार पर रोक लगानी होगी, वैसे आपने कई चीजों के वादा बाजार पर रोक लगाई है। यह आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ, उसमें कहा गया था कि वादा बाजार में जिन जिंसों पर रोक लगाई गई है, उस पाबंदी को उठा लेना चाहिए, इस बात की सिफारिश की गई थी, इसीलिए हमको डर लग रहा था। मुझे खुशी है कि कोई टेक्नोक्रेट, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना, जब प्रणब बाबू, फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो हमको थोड़ी सांत्वना मिली, नहीं तो जिन लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया था, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़कर यह लग रहा था कि ये लोग देश को बेच देना चाहते हैं, यह हालत थी।

इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि आप वादा बाजार पर रोक लगाइए। आपने अभी Food and Civil Supplies Department में एक कमीशन बना रखा है, उसमें कोई जान नहीं है, वह toothless है, वह नियंत्रण करने में बिल्कुल अक्षम है। आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना चिंतित रहते हैं।

टाटा, बिरला के शेयर का दाम बढ़ता है या Reliance के शेयर का दाम बढ़ता है, तो इस देश के 99 प्रतिशत लोगों को उससे क्या मतलब है? जिसमें पांच-सात लाख लोगों का interest involve है, उसमें तो आप इतनी रुचि दिखाते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: तिवारी जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री शिवानन्द तिवारी: आप उसको regulate करने की कोशिश करते हैं और वादा बाजार इतना व्यापक है, इस बारे में आप क्या करते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: तिवारी जी, आप समाप्त कीजिए। Please conclude.

श्री शिवानन्द तिवारी: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं पी.डी.एस के बारे में कहना चाहता हूँ। आप इस पी.डी.एस. के जरिए दाम को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। महोदय, चिंताजनक बात यह है कि पी.डी.एस. में उठाव हर साल घटता जा रहा है ...**(समय की घंटी)**... मेरे पास उसके आंकड़े हैं कि यह लगातार घटता जा रहा है।

श्री उपसभापति: आप कितने आंकड़े देंगे, अब आप समाप्त कीजिए, दूसरे भी सदस्य बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

श्री शिवानन्द तिवारी: महोदय, मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी यहां मौजूद हैं। आपके सामने इतना बड़ा अन्न का भंडार है। आप उसे ओपन मार्केट में क्यों नहीं बेच रहे हैं?...(समय **की घंटी**)... आपने पिछले साल न के बराबर ओपन मार्केट में अनाज बेचा है। अगर ओपन मार्केट में अनाज उपलब्ध रहता, तो आज इतना दाम नहीं बढ़ता ...**(समय की घंटी)**... ।

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री शिवानन्द तिवारी : महोदय, मैं चौथी बात कहना चाहता हूँ कि आप कृषि में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें निवेश कीजिए ...**(व्यवधान)**... किसानों को इन वायदा कारोबारियों के हाथ में मत छोड़िए, नहीं तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me the opportunity. At the village level, or *moffosil* or city level ...*(Interruptions)*... every where the people, more so the people of middle class, are suffering very much because

the working class, that is, the below poverty line people, are protected in certain ways in certain States. The States, which are very much interested in the people's welfare, could bring forth certain new ideas by giving not only rice but also certain other grocery items in certain ways through the fair price shops. We can take the example of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Both the States are giving very important *dal* and other materials, which are used for daily food purposes, through the fair price shops. But, at the same time, we have to consider the fact that production of food materials, grains and other things is now being taken away from the villages by the traders who convert it back into different machine-made food materials and sold such material in the same market. Similar things happened during the colonial rule. We used to produce all the material which was taken away to their own country, England. This material would come back with new packages and for more prices to be sold in the same market of India. For that only, we agitated and brought our independence. Now, in the global economy, all the agriculturists work and their production is taken away by the traders and sold back with multiple prices in the same villages. In these circumstances, Sir, the Government of India, more so the UPA Government, has initiated great programmes like NREGA. Through these programmes, the common man could get the purchasing power for getting his own food material and other needs by his own hard work. Previously, people used to migrate from one place to another for getting employment, but nowadays employment is given in their own villages. Therefore, the purchasing power is increasing. But, at the same time, the small farmers and the medium farmers could not withstand certain wage increase. Therefore, they are not going for agriculture. They could not expect water or irrigation facilities at appropriate time. The fertilizers are not reaching the villages at appropriate time. The wages of the labourers, who are migrating from place to another, are more than what is needed. Mechanised ways of ploughing, harvesting, everything is of high cost. Therefore, the agriculturist, who could not maintain that type of expenditure, is leaving this and migrating to the nearby urban area. Therefore, this matter needs to be looked into by the Ministry of Agriculture.

Previously, massive agricultural production programme was implemented. People having land holdings were helped by giving bank loans at appropriate time for developing agriculture. But now banks are not willing to give loans to villagers. Therefore, people are migrating and seeking jobs elsewhere.

Food material available in villages is not accepted by various programmes. For example, two days ago, UNICEF announced that it wanted packaged material to be supplied to children throughout India. But this is a method of robbing village people of their produce and taking it to other countries, packaging it, and then selling it back in India. This is the main cause of poverty in villages. In villages, there should be markets for their own produce whether it is grain or milk or any other product.

Now purchasing power of the people in villages has increased. But markets for their produce in villages have decreased. Markets have now moved to the urban areas where traders

are taking away all the produce, including milk. They are taking it to the urban areas and coming back with mixed milk. Even milk powder is sold in the villages rather than pure milk. I can say this because I myself come from a village. Ninety per cent of the people in villages are not using milk which they have in their own village. They are selling it because they need money for their day-to-day affair. The Government has to see to it.

Sir, the Central Government is blamed for everything. When there is a rise in the prices of essential commodities, the onus is on the State Government. We cannot ask the Central Government for everything. The Central Government can control the price of steel or the price of cement or prices of some other commodities.

Creating markets for locally produced raw material is in the hands of the State Government. The State Governments should take up this issue genuinely. They have to see that markets are created in villages and their own material is sold in nearby places, so that the cost of transport can be reduced and some other costs can be reduced. *Gram Rajya* has to be established.

We are providing huge allocations for Panchayati Raj institutions. The State Governments have to take care of that aspect. The price rise has now become just like law and order problem, even though it is the responsibility of the State Governments. Nowadays everything is pushed to the court of the Central Government. Very often Central Ministers come forward with law and order problem and also price rise as if they are accountable for that. Really, they are accountable for controlling cement price and steel price. How can the Central Government control the price of milk in a particular area or a particular State? It is the subject of the State Government. The State Governments are simply pushing the ball in the court of the Central Government. They have to think about it. They are responsible and accountable to local people. Panchayati Raj Institutions have not been given full power. They do not enjoy all the powers which were enunciated in the amendment to the Constitution. Twenty-nine subjects were not given to the Panchayati Raj institutions. If the system of Panchayati Raj is properly implemented, they will control their own products, they will create markets for their own products in that area. That is also insufficient, Sir. For that also, the Central Government has to compel. When it releases the funds, it has to see whether the Panchayati Raj institutions are alive; whether they are enjoying the powers; and whether the elected representatives of the panchayats have the power to control their own destiny. If that is so, then only funds should be released. Otherwise, funds should not be released. The Central Government has to see that dynamic Panchayati Raj institutions come up in villages. Similarly, Sir, the State Governments should come forward to implement their laws.

Yesterday, 'Slumdog Millionaire' was shown in Parliament. I saw it for half an hour. Afterwards, I could not tolerate those scenes. The scenes in the movie show, to my knowledge, that more than 150 laws of the Central Government and the State Governments are violated in

that area. That was shown in the movie. This movie has got the Oscar awards. We are celebrating it. The movie shows that everybody starting from a Member of Mumbai Corporation to a Member of Parliament, even Prime Minister, is violating the law. That is why this movie got the Oscar awards in various categories.

This is not a good thing for our country. *...(Interruptions)...*

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Sir, he has used the word 'Prime Minister'. Please expunge that. He said that unknowingly. Please expunge that. *...(Interruptions)...*

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: I am only talking about the movie. *...(Interruptions)...*

PROF. P.J. KURIEN: Sorry, sorry. *...(Interruptions)...* Okay, it is about the film. *...(Interruptions)...*

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, I am not blaming any Prime Minister or any Chief Minister. *...(Interruptions)...* I am only saying that, that film shows as if everything is violated. The result of his suffering and knowledge makes him a billionaire. That is what I want to tell. The overall picture is that we are violating the laws and we are not implementing the laws properly. Therefore, the result is, Slumdog Millionaire movie. That is what I want to say. If we properly implement the laws....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please come to price rise. *...(Interruptions)...*

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: We want to shut our eyes on everything but we celebrate the successful showing of Slumdog. Throughout the world, it is said that India is like this. *...(Interruptions)...* Therefore, price rise is one of the issues. I am just explaining.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Price rise is the only subject for discussion.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, I am explaining the situation that if laws are properly implemented, even the price rise in Mumbai will not happen. All the facilities will be given to Mumbai. We are expending huge money on everything. But, it is not reaching the common man. That is the main reason for price rise. Thank you, Sir.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I wonder whether we are going to achieve anything from this. I am saying this based on my past experience also. It is not to blame one Minister or one person. People are asking: Has it become a ritual? You discuss price rise. You express your concern or agony. But, nothing is happening. If you see for the last three years, the inflation rate is coming down. But, the market prices are going up and there is no explanation whatsoever. How are WPI and CPI functioning? I wish the Finance Minister were here. But, he came here and told us that he had to go for the CCS meeting. I think, there will be a meaningful discussion if both the Finance Minister and the Agriculture Minister are present in

the House. Most of the things are in the hands of the Finance Minister and some are in the hands of the Commerce Minister. The Agriculture Minister alone will not be able to solve the problem. It is the collective responsibility. *...(Interruptions)...* He told me that there was some meeting. My only urge is that we must do something serious rather than simply sympathising with the people or just deriving satisfaction that I also spoke on the issue of price rise in the House. We are not going to achieve anything. The Government is not able to do anything. Sir, just now, my friend, Shri Sudarsana Natchiappan was saying as to what the Central Government can do. Sir, I also understand that the States have a responsibility. But, under whose control cement comes? Under whose control steel comes? Steel and cement prices in the world market have come down whereas here, people have formed a cartel. An increase of Rs. 7000 in steel prices! Today, a cement bag costs Rs. 250. Why? Is there shortage of production?

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, actually, the NDA Government increased it from Rs. 800 to Rs. 2000.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, during the NDA Government, if you want to see the record, all prices were under control. There was no line, no queue, no waiting list, no shortage, no black-market, etc. Today, everything is there. I am not entering into an argument on that issue. My point is, the Government has miserably failed to contain prices. The common man is allowed to suffer year after year. My worry at this time is, there is loss of jobs, growing unemployment and recession on the one side which is affecting mostly the middle class and on the other side, the deficit in monsoon is going to add to the woes of the people. This is aggravating the problem and we must understand it. We must have a multi-dimensional and multi-pronged approach to face this reality. Otherwise, we will not be able to do justice. The latest figure shows that the paddy cultivation would go down by 20 per cent because of deficit monsoon. Our noted agricultural scientist and expert, Dr. Swaminathan, opined that there might be a decline of 15 per cent in rice production in the country. That means the situation is going to be further aggravated. We are all aware and you calculate the price index that 55%-60% of the budget of the common man accounts for food items. The other things account for only 45 per cent. Fifty-five per cent to sixty per cent accounts for food items. Today, the prices of almost all the food items are increasing. The Government of the day should plan beforehand if there is going to be a shortage of crops. You have the Meteorological Department; you have your own Agriculture Department; you have the Department of Consumer Affairs also. You have to calculate how much is going to be the production and how much is going to be the demand. Then, if the production is going to go down, beforehand you have to plan for importing from outside, from wherever it is possible; if it is going to be surplus, then you plan for export. What is the Government doing in this regard? There is shortage of pulses; there is shortage of cereals. The foodgrain production, of course, was excellent last year thanks to our agriculturists. We salute them. This year, there is going to be a shortage. If there is a shortage and if there is no

alternative plan or contingency plan for the Government, this is the situation. I would also like to know from the hon. Minister what the Government of India has done, particularly, with regard to cereals, pulses and foodgrains, to increase the production, to preserve enough stocks and to see that there is no hoarding in the market. As far as hoarding is concerned, I do admit that the State Governments have a role to play. It is not to play politics because in India, fortunately or unfortunately, every political party of the spectrum largely is ruling in one State or the other. That being the case, there has to be a collective effort to come to the rescue of the common people which we are not able to do. The Government of India, being the leader of the Government of the country and also the policy and decision-making body at the national level, is not able to do anything. Are we so helpless? That is the question I am asking myself. As I have said in the beginning itself, I don't want to derive satisfaction by blaming one Minister. Are we helpless? Is the Parliament of India helpless? The prices are going up every day. When the prices start going up, the political game begins. The other day also I said that my Andhra Pradesh Government had given an advertisement that the prices in other States were higher than in Andhra Pradesh. That is not the solution. The prices are higher in Maharashtra, in Delhi and in Karnataka, according to the Andhra Pradesh Government's advertisement. They have released a half page advertisement in all the newspapers. That is no solution. That is not going to solve the problems. Today, the situation is that the price of every item, particularly, food items, is going up and we, in the Government or in the Parliament, are not able to do anything. This is the major worry for the people.

Another issue is about WPI and CPI. How do you correct it? The other day, the Prime Minister's Economic Advisory Council Chairman, Mr. Suresh Tendulkar, had said that the WPI is an unsatisfactory indicator of inflation that has dented the credibility of the Government data following its divergence with the consumer price. It is a reality. He has accepted it. The other day, even the Finance Minister on the floor of the House had accepted it. It is high time that we corrected it and correlated it with the Consumer Price Index. The data, the series, for the Wholesale Price Index are released weekly, whereas we release the data for the Consumer Price Index monthly. Why? As far as the WPI is concerned, the series are released in a transparent manner, but, as far as the Consumer Price Index is concerned, they are not transparent. I don't know what the reason for this differential approach is.

Now, coming to the common man's idli, the ordinary road-side idli, earlier we were getting it for Rs. 4; today it has gone up to Rs. 8. I am not talking of the idli of the middle class or the upper middle class. There are people who push the small carts and sell idli at Rs. 4. That has now gone up to Rs. 8.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sambar has become costly.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sambar has become costly because the price of Arhar Dal has gone up. Why I am giving this small example is that when the price of idli has gone up from Rs.4 to Rs.8, which means that there is a 100 per cent increase, what will the poor wage earners

do? What will happen to a poor student, who will have to travel long distances to reach a school or a college, and who depend on these dhabas? How is he going to face the situation? This is an issue which is really worrying us. There is another argument that there are foodgrains available in the godowns. There is also a news item, which appeared in many of the newspapers, that stocks of pulses rot in major ports, as the prices have shot up. In the Kolkata ports and other ports, lakhs of tonnes of pulses and sugar worth around Rs.1600 crores are lying unclaimed. If it is true, then, it is a horrible situation, an unpardonable act. You are getting arhar dal at Rs. 95, and the same thing has been imported and stocked in the ports, and we are not able to do anything. Nobody seems to be concerned about it. In fact, we have the Cabinet Secretary and the hon. Agriculture Minister saying that they are not aware of this. I would like the Government to immediately order an inquiry into this, and I will be happy if the Minister responds to this. If this is true, then, it is a very serious matter. Then, the price of jowar has increased by 16 per cent; bajra by 17 per cent, pulses by 15 per cent, ragi by 28 per cent and moong by 18 per cent. The prices of all vegetables also have gone up. The price of tea has gone up by 30 per cent. The price of sugar is Rs. 27 per kg. The farmers are in a difficult situation. Now, is there a shortage of sugar? Now, there is a report that the crop production earlier was 240 lakh tonnes, and this has come down to 150 lakh tonnes. If this is so, then, it is another disturbing factor because we cannot live without sugar. It is a different matter that people, who are diabetic, may not need it. But, fortunately or unfortunately, nearly 60 per cent of the people are out of this range. So, sugar is also an important item. I would like to know what is being done with regard to sugar. Then, with regard to dal, if there is shortage in dal, particularly, Red Gram Dal, then, we should have plans to import it from countries where there is production. The reason given by the sources in the Government is that there is a decline in production in those countries too. My point is, you must first analyse what the basic, nutritious food requirements of the people of our country, whether there is shortage of these foodgrains and how to encourage increased crop production. Fortunately, we have both the Agriculture Minister and the Commerce Minister planning for crop diversification. But how long is it going to take? What is our strategy for this? Did the Cabinet Committee on Prices apply its mind in depth? Have you any contingency plan, any long-term plan, to see to it that proper production of, at least, the foodgrains, is made. This is one aspect. Then, coming to other items, there is no shortage of rice as of today. It may be 15 per cent less next year. Even then the rice is priced at Rs. 35-40 a kg. How do you expect the middle class and the lower middle class people to survive? Everybody is not a BPL cardholder. This has never happened before. My friend was talking about the NDA regime. It was only Rs.18-20 at that time. Now, I am not deriving satisfaction saying that prices were less at that time and the prices are more now. That is why this Government is becoming unpopular. Anyway, being popular or unpopular depends on many issues. People of this country do not vote on the basis of their actual sufferings. They vote on different parameters. That is the irony of this country. Coming back to the main issue, the prices of all basic requirements of day-to-day

consumption have shot up, and the Government is not able to do anything to contain the prices. The prices of vegetables have gone up. One can say that this is a seasonal phenomenon. But, there also, there is so much exploitation going on. And, there is no information available to the producer, nor to the consumers, as to whether production in respect of foodgrains has gone up or come down, or, whether there is shortage or whether there is surplus, etc. These kinds of information should be available to the people.

Then, Sir, we have always discussed about the need for improvement in the cold storage system in the country so that we can store perishable items, and then, transport them to the areas where they are needed. We have regional variations in the country. Tomatoes in my part of the country, in Chittoor district of Andhra Pradesh, are being sold at one rupee a kilo. Today, in Delhi, tomatoes are being sold at Rs. 16 to Rs. 20 per kilo. It is the same country, from Madanapalli to Delhi, but look at the exploitation that is going on! We must have some approach, particularly, to give more push to cold storage systems. Coming back to the issue of Centre and State coordination, enquiring from the States what is required there and what is in short supply and, then, rushing stocks to those States, is the responsibility of the Central Government. And the Central Government, I must say, has miserably failed in its responsibility.

Then, coming to the issue of planning for the future, I will be happy if the Minister takes the House into confidence and gives an assurance how he is going to solve this problem because, as per this year's indication, the production of rice, pulses, cereals and even sugar is going to come down. This is another issue. Then, coming to the issue of the present situation, what is the system through which the Government of India is planning to tackle this situation about shortage, about storage, about black marketing, about exploitation by middlemen and so on. These are issues that naturally agitate the minds of the people. It is the duty of the Government of India, and I do not like the Government of India to throw this responsibility on the States and, then, wash off its hands, because the Central Government has the authority and it is the decision-making body. Sir, I must say on record that the UPA Government, after presentation of the Union Budget, was totally silent on how it is going to tackle the spiralling prices of foodgrains, especially pulses. There is no mention of this and the Government seems to have forgotten the *aam admi* after having benefitted from his support. And now, the unprecedented fall from the double digit to the single digit of the WPI is not reflected in the Consumer Price Index. This is an irony. First of all, is the Government going to address this issue? Then, coming to the situation where...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How long will you take?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am going to conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two more speakers.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I know that, Sir. As I said, continuously speaking on the issue is not going to help me or the cause. My point is that going by indications, there are going to be shortages; one is the shortfall in sowing; the other is shortfall in production because of untimely rains. Now, what is the contingency plan of the Government to contain the prices? If I have to say in one word what the common man is feeling, I would say that people are weeping and the Government is sleeping.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, we are extremely glad that, ultimately, a serious issue is being discussed here. Few days back, MPs from the Left and from some other political parties took part in a demonstration on this serious problem and on the miseries of the common people. Sir, today, in a daily newspaper, a news item has a headline 'Rise and Rise of Prices. Then, in the news item, they quote prices of various items in the metropolis; for example, arhar dal was Rs. 48 per kg and it is now Rs. 86 per kg; moong dal was Rs. 46 per kg; it went up to Rs. 50 and then to Rs. 70 per kg within one year; similarly, kala masoor also went from Rs.48 to Rs. 70 per kg. I would not like to go into all the details that the newspaper has given. The news item also asks people to talk to them and tell them how the price rise is hitting them and how they are managing to make both ends meet. This question was asked in the news item. Our question is: how are 77 per cent of the people earning below Rs.20 a day managing themselves? Who will answer these questions?

Sir, according to the recent Human Development Report, which says, 'that nearly 50 per cent of the world's hungry people live in India. Around 35 per cent of India's population is considered food insecure, consuming less than 80 per cent of minimum energy'. And, we all know the Arjun Sengupta Report. Sir, on 18th July, 2009, food inflation went up by 1.2 per cent in just one week. The maximum increase was seen in wholesale price of vegetables, which rose by 4.9 per cent; followed by pulses, that went up by 4.2 per cent; meat, egg and fish rose by 3.5 per cent in just one week. There was an increase of 3 per cent in Moong and Masoor and an increase of 2 per cent in Arhar during the week. Arhar has reached this psychological mark of Rs. 100 a kilogram in most retail markets. This is the picture in all the retail markets of all the metropolis. Sir, is there any way out, I ask, other than being hungry for a person earning less than Rs.20 a day? Studies worldwide show that the hungriest of the people are the producers, the farmers, and India is no exception, Sir. Suicide is continuing among today's farmers of our country. They have no capacity to borrow, and the purchasing power is declining seriously. We know the real picture. This is what is being faced by millions of aam aadmi in our country. This is happening at a time when the wholesale price index is in negative and the consumer price index is growing at a rate over 77 per cent. This mismatch in itself, Sir, has serious implications and reflects a deep structural defect in our country. The joblessness arising out of recession has worsened the situation. The purchasing power is coming down, and looting of the people is the picture of today, of our dear country. So, this is the real picture, Sir.

Sir, this unprecedented price-rise is, primarily, due to — and we ask the Government to answer — the large scale encouragement being provided to speculative trading in the commodity exchanges through futures trading in essential commodities. The Forward Markets Commission of India, in its Fortnightly Report, informs that the total value of trading at the commodity exchange between June 1 and June 30, 2009 was Rs. 15,64,114.96 crores, while the same was Rs. 2,21,888.06 crores in June, 2007. In other words, the total volume of trading in the Forward Markets, within these two years, jumped by over seven times. Therefore, the only way, that profits can be made from such huge value of trading, is to ensure that prices of those commodities rise relentlessly, mercilessly burdening the people. And, this is, exactly, a Ram Rajya for these speculators and the rich, Sir. And the Government, instead of doing the needful, is doing the opposite. It has abolished the Commodity Transactions Tax, and we want an answer from the Government and the Minister.

Sir, I would like to draw the attention of the House to the website of the Department of Consumer Affairs, Government of India. In the said website, there is a High Level Committee Report. The High Level Committee, in its recommendations states, *inter alia,* “that a system of universal PDS is being reintroduced with uniform Central issue price, one each for rice and wheat, respectively, for all consumers, in all parts of the country.” The Union Government, Sir, is squarely responsible for the present state of affairs. Sir, see the definition of BPL in the present scenario. The definition of BPL is being manipulated in such a manner that crores of people will be left out from receiving foodgrains and other essential commodities at affordable prices. The existing benefits under the *Antodaya* Scheme are being curtailed.

Sir, I have three specific questions to ask. Another MP of my party will speak on the subject. But I have only three specific questions to ask. I would like to know whether the Government will agree to ban all future and speculative trading in essential commodities which is being continuous demanded by the Left parties and some of the other political parties here. I would like to know whether the Government would agree to introduce universal PDS for all. Also, I would like to know whether the Government would agree to guarantee food security for all. Thank you.

श्री उपसभापति: श्री जनेश्वर मिश्र।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): सर, मेरे पास कितना समय है?

श्री उपसभापति: आपके पास 10 मिनट हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखण्ड): सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कल राखी पूर्णिमा है। जिन लोगों को गाँव जाना है, अपने इलाके में जाना है, बहनों के घर जाना है, अगर हाउस देर तक चलेगा, तो उनके लिए मुश्किल है। मेरा आपसे आग्रह है कि आज अधिक-से-अधिक 5.30 बजे तक छुट्टी कर दें और इस विषय को continued कर दें।

श्री उपसभापति: यह continued इसलिए नहीं हो सकता कि अब हमारे पास दो ही दिन बचे हैं।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): सर, हम 6 तारीख को देर तक बैठ लेंगे।

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Clarification on sugar imports is very important. We need to have clarifications. We can keep that on the following day, Sir.

श्री उपसभापति : क्या आप बैठने के लिए तैयार हैं कि आप 10 बजे तक भी बैठेंगे, 11 बजे तक भी बैठेंगे?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, we do not have any problem even to sit up to 10 o'clock. Please try to understand the sensitivity, Sir. Rakhsha Bandhan is a function wherein we not only go to Bangalore but also to the villages and the nearby places.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have no problem. The only thing is, whatever agenda...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the Minister will respond. He knows this. *...(Interruptions)...*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, we agree with the sentiments expressed. We request you that we can sit till 6 o'clock. *...(Interruptions)...*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it would look a little odd, but some of the flights take off at 6 o'clock. सर, इसको 5 बजे खत्म करिए और इसको परसों लीजिए। परसों हम लोग बैठेंगे।

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, the clarification on the sugar imports is important; so, kindly schedule it for another day according to the convenience of the Minister. *...(Interruptions)...* When will it come up?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the next two days, we will have to do it. There is no other way.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, the business that we plan to have for the other two days would come in the way!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only two days are left. If you all decide to sit a little late, the business can be completed. Moreover, self-restraint on time! जनेश्वर जी, आप बोलिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, जब सदन में इस पर बहस आगे बढ़ेगी, क्या तब भी हमारा समय 10 मिनट ही रहेगा या थोड़ा टाइम बढ़ाया जाएगा?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त लोग कह रहे हैं कि ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The decision is that we finish the first round, adjourn and then take up the next round on Thursday.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, Thursday evening?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Thursday evening.

SHRI SHARAD PAWAR: Sugar discussion on Friday? I have no objection to that, Sir. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: These are the things and we will work out the agenda.

SHRI SHARAD PAWAR: My only request is, the day after tomorrow we have to sit late in the evening because there is a discussion on the same subject in the other House also. *...(Interruptions)...*

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, हाउस कितने बजे तक चलेगा?

श्री उपसभापति: एक राउंड हो जाने के बाद हम adjourn करेंगे। हम स्पेशल मेंशंस ले करा देंगे। जनेश्वर जी, आप बोलिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: उपसभापति महोदय, इसी सिलसिले में दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि कल राखी का त्यौहार है। राखी का त्यौहार बहनों का त्यौहार होता है, बहनें अपने भाइयों को मिठाई खिलाती हैं ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती वृंदा कारत: पैसे कहां है?

श्री जनेश्वर मिश्र: इधर जो हम लोगों के घरों में मिठाई बन रही है, उसमें इतनी कम चीनी पड़ रही है कि वह बहुत फीकी हो गई है। जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन सबने यही कहा कि अब आप शुगर के मरीज़ हैं, आप कम मीठी मिठाई खाइए। इसीलिए सरकार भी चाहती है कि इस पर बहस टाली जाए।

सबसे पहले मैं अपने मित्र शिवानन्द तिवारी जी को कुछ बताना चाहता हूं। इन्होंने एक घटना का जिक्र किया था कि बहुत दिनों पहले लोक सभा में एक बहस चली थी, 'नेहरू बनाम लोहिया'... लोहिया जी ने यह कहा था कि 27 करोड़ आदमी तीन आने पैसे पर गुजर कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी ने इस बात से इंकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि नहीं, 27 करोड़ लोग क्या पूरे देश के लोग 13 आने पैसे पर जी रहे हैं। उस समय इस पर एक लम्बी बहस हुई। उस समय श्री गुलजयरी लाल नन्दा साहब प्लानिंग मिनिस्टर थे। उन्होंने इस पर बड़ी खोज की और फिर सरकार की तरफ से बताया कि तीन आने पैसे पर तो नहीं, हां, सात आने पैसे पर देश के 27 करोड़ लोग गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद भी लोहिया जी ने यह साबित किया था कि नहीं, तीन आने और उससे कम पर भी लोग गुजर कर रहे हैं।

उपसभापति महोदय, जब कभी भी हम लोग महंगाई और अभाव पर बहस करते हैं, तो हम यह जानते हैं कि कोई बगावत नहीं होने वाली है। अगर आप दाल बहुत महंगी कर देंगे, तो हम बिना दाल के रह जाएंगे। दस दाने दाल के डालेंगे और उसमें टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, लौकी डाल देंगे और कहेंगे कि दाल खा रहे हैं। हिन्दुस्तान का आदमी अभाव में जीना जानता है। भोजन के अभाव में वह जल्दी दम तोड़ना नहीं चाहता और इस बात को गद्दी पर बैठे हुए लोग भी समझ जाते हैं। कभी भी महंगाई के सवाल पर बगावत नहीं हो सकती है, हां, भूख के सवाल पर हो सकती है।

जब इस देश में अंग्रेज थे, उस समय 1902 में उन्होंने एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया था और तब से यह कानून आज तक बदला नहीं है। बीच में 1967 में Producers Price Index आया था, लेकिन वह भी लगभग वही था। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि जो लोग सामान तैयार करते हैं, उनके पैमाने पर भाव तय किया जाए। केवल हिन्दुस्तान में ही ऐसा होता। यहां पर सामान तैयार करने वाले के

पैमाने पर भाव तय किया जाता है, सामान के खाने वाले और उपभोग करने वाले के पैमाने पर नहीं किया जाता। पाकिस्तान तक में यह इतना नहीं होता है, इंग्लैंड में तो बिल्कुल नहीं होता। जब मैं सामान की बात कर रहा हूं, तो केवल गेहूं, चावल या दाल की बात नहीं कह रहा हूं। बाजार में केवल गेहूं, चावल और दाल ही नहीं बिका करते हैं, उपसभापति महोदय, बाजार में लोहा भी बिकता है, सीमेंट भी बिकता है, पेट्रोल भी बिकता है, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा।

सब चीजों के दाम कैसे चढ़ते हैं? जिसने उसे पैदा किया, उसका जितना खर्चा पड़ा, जिसे कॉस्ट फैक्ट्री प्राइस भी कहते हैं, उसकी बुनियाद पर दाम तय कर दिया जाता है। कभी भी उपभोक्ता के दाम पर यह भाव तय नहीं किया गया। 1907 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो हम क्या बता सकते हैं, लेकिन इसके बाद यह मुल्क तबाह होता चला गया। उसके बाद से लोगों के पास बहुत सी तकनीकें आ गईं। कल-कारखाने में जो उत्पादन करते हैं, उनको पैसा कमाने के क़िस्म-क़िस्म के तौर-तरीके भी मालूम हैं।

यह बात सही है कि जहां कई किस्म की खेती हुआ करती थी, धीरे-धीरे वह बारीक खेती पर आती चली गई। यह बात भी सही है कि खेती की पैदावार की खरीद के लिए कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियां भी आ गईं, जो वायदे के आधार पर खरीद करती हैं। यहां मैं छोटी-छोटी कंपनियों की बात नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां, देश के बहुत बड़े-बड़े लोग इस क्षेत्र में आ गए हैं। अब तो अमरीका का एक बहुत बड़ा स्मगलर टाइप का आदमी भी इसमें आ गया है, जिसकी खरीद पर अमरीका ने भी रोक लगा दी थी कि इससे आगे आप नहीं बढ़ोगे, लेकिन भारत सरकार ने पिछले दिनों उसका स्वागत किया। जितना उसका अकेले का कारोबार है, उतना तो हमारे देश का सारा खुदरा कारोबार है। उसका पूरा साम्राज्य फैला हुआ है और उसका नाम है वालमार्ट। हम जानते हैं कि सरकार उसको जानती होगी। ये सब-के-सब चले आए। जिस तरह से ये लूट रहे हैं, उनको मालूम होता है कि दाल की कमी पड़ने वाली है। पता नहीं वे कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं? उसके बाद कानपुर की मंडी में जितनी दाल है, दाल-मंडी के मालिकों से कहा कि कितनी दाल है, जवाब मिला कि इतनी है। तब उसने कहा कि इतना रुपया हम भेज रहे हैं, दाल की बिक्री रोक दो। तब बाजार रुक जाता है, थम जाता है। सरकार को कहीं-न-कहीं इसके बारे में, वायदा कारोबार के बारे में, कुछ करना चाहिए। इन्होंने पिछली बार गेहूँ को वायदा कारोबार से मुक्त कर दिया था। गेहूँ के कारोबार पर रोक लगा दी थी और चीनी पर से यह रोक हटा दी थी। अब हम लोग चीनी की दुर्दशा देख रहे हैं। इसी तरह से एक-के-बाद एक आइटम बदलता रहता है। यह सच है कि हमारे यहाँ दाल कम पैदा होने लगी है। हमने खेती का रुझान दूसरी तरफ कर दिया, लेकिन खेती की पैदावार अकेले तो बाजार में बिकेगी नहीं। जो अनाज बेचेगा, वह ईंट खरीदना चाहेगा, वह लोहा खरीदना चाहेगा, वह सीमेंट भी खरीदना चाहेगा। — सर, मेरे दस मिनट मत देखिए, वरना मेरी बात अधूरी रह जाएगी।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। मैंने उसे उठाकर उस तरफ रख दिया है।

श्री जनेश्वर मिश्र: ठीक है, सर। इस तरह वह ये चीजें खरीदना चाहेगा। जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, तब हमारे पिता जी एक बोरा गेहूँ बाजार में ले जाते थे और उधर से ईंट के भट्ठे वाला 10 हजार ईंटें दे जाता था, उसको वे उसका पैसा दे आते थे। उस समय एक क्विंटल गेहूँ पर 10 हजार ईंटें मिलती थीं। आजकल एक क्विंटल गेहूँ बहुत कम पैसे का हो गया है, एक हजार रुपए का, लेकिन गाँव में एक ईंट चार रुपए में बिक रही है। हम लोग तो सरकारी मकान में रहते हैं, इसलिए हमें ईंट का कोई मोह नहीं, सीमेंट का कोई मोह नहीं और लोहे का भी कोई मोह नहीं, क्योंकि सरकार के खजाने से हम लोगों के मकान बने हुए हैं। वे बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं, हमने देखा है। लेकिन, यह जो कुछ भी रुपया सरकार के खजाने में आता है, वह देश की आम जनता की जेब से आता है। जिसको उस रुपए का दर्द होगा, देश की आम जनता का दर्द होगा, वह ईंटों का टूटना-फूटना देख करके तिलमिला जाता होगा। आज चार रुपए में एक ईंट बिक रही है, जबकि किसी जमाने

में एक बोरा गेहूँ ले जाकर बेच देने पर 10 हजार ईंटें मिलती थीं। ईंट उसी मिट्टी की बनती है। उसे जरा-सा मशीन पर चढ़ाया, थोड़ा-सा कोयला लगा और जब वह पक गई, तब उसकी कीमत बढ़ने लगी।

सर, जब मैं पहली बार पार्लियामेंट का मैम्बर बनकर आया था, तब मैं अपनी जीप चलाने के लिए एक रुपए का एक लीटर पेट्रोल या पाँच रुपए का एक गैलन पेट्रोल खरीदता था और यहाँ आकर हम लोग इंदिरा जी के खिलाफ नारा लगाते थे कि 'यह इंदिरा का शासन है, सवा सेर का राशन है' उस समय एक रुपए का सवा सेर गेहूँ बिकता था और एक रुपए का एक लीटर पेट्रोल भी बिकता था। मैंने पाँच रुपए का एक गैलन कहा है। आज पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो गया, लेकिन हमारा गेहूँ 10 रुपए प्रति किलो ही रह गया है। कहीं-न-कहीं कारखाने के सामानों के भाव और खेती की पैदावार के भाव में कोई अनुपात रहेगा या नहीं रहेगा? कितने दिनों तक पक्का माल तैयार करने वाले कच्चा माल तैयार करने वालों को लूटते रहेंगे, इसका जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा? यह मूल्य सूचकांक का नियम 1907 का बना हुआ है। अब तक कितनी पुश्तें चली गईं, कितनी सरकारें बदल गईं, लेकिन हम लोग उसको बदल नहीं सके। केवल उपभोक्ता के पक्ष में सोचा जाएगा? केवल उत्पादक के पक्ष में सोचा जाएगा? जब मैं उत्पादक के पक्ष में सोचने की बात करता हूँ, तब कुछ मित्र तो कह देते हैं कि चंदा खाया जाता है, राजनीति महँगी हो गई। मैं यह आरोप नहीं लगाता। लेकिन, सरकार कच्चे माल पर टैक्स लगाती है और वह टैक्स फैक्टरी से जोड़ कर हमारी जेब पर आता है। इस तरह, दाम के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। हमें नियम बनाने पड़ेंगे कि खेती की जो कोई भी पैदावार तैयार होती है, उसके एक सेर पर 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे या 50 पैसे रहेगा और दूसरी फसल तक इसमें देश भर में हेर-फेर होने नहीं दिया जाएगा। इसे एक रुपया कर दो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। दो फसलों के बीच में दाम तय होने चाहिए, वरना हिन्दुस्तान में खेती की पैदावार की चीजयें के भाव कभी तय नहीं हो सकते।

दूसरे यह कि किसान की पैदावार सब खाते हैं, हम MPs भी खाते हैं, कैबिनेट सेक्रटरी भी खाता है, इंजीनियर भी खाता है, कलैक्टर भी खाता है और मजदूर भी खाता है। सभी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए चूंकि उसकी चीज आपको सस्ती बिकवानी जरू री है, तो बिकवाइये, लेकिन उसकी पैदावार में जितना खर्चा होता है, उतना तो उसको अपने खजाने से दे दीजिए! दो-चार रुपये मुनाफा जोड़ कर दे दीजिए तो और अच्छा है। किसान को कुछ नहीं मिलता है। वह 1200 रुपये या 1300 रुपये प्रति क्विंटल की लागत पर गेहूँ तैयार करता है, लेकिन उसे 800 रुपये में बेचना पड़ता है। गांव के किसान का खपरैल कभी ठीक नहीं होता। अगर उसका बेटा कोलकाता चला जाए और वहाँ पान की दुकान खोल ले तो उसका खपरैल पक्का मकान बन जाता है। अर्थव्यवस्था के इस पेंच को कृषि मंत्री को और जो कोई भी सरकार चलाएगा, उसे भी समझाना पड़ेगा कि गांव उजड़ा-उजड़ा क्यों रह गया? अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम मार खा जाएंगे, हम कभी सुधार नहीं कर सकते। गांव का किसान महंगाई का मारा है। सर, वह किसान जिसने अपना गेहूँ बेच दिया, क्योंकि उसे बेटी की शादी करनी थी या जमींदार को लगान देना था, तीन महीने बाद जब घर में रोटी नहीं रहती तो वही किसान अपना ही गेहूँ खरीदने के लिए लाइन में खड़ा होता है। क्या उसकी इस बेबसी के बारे में कभी सोचा नहीं जाएगा कि वह लाइन में खड़ा रहे? आज बहुत सी बहनें हैं जो अपने भाई के हाथ में राखी बांधते समय तश्तरी में जो मिठाई रखती हैं, उसकी मिठास की कमी का अहसास कर रही हैं। भाई और बहन की राखी का संबंध तो बड़ा पवित्र था। भाई उसकी रक्षा का पक्का वादा करता था। आप सोचिये कि अगर बहन फीकी मिठाई खिला देगी तो उसका यह पक्का वादा कितना कच्चा वादा हो जाएगा? मानवीय रिश्तों के साथ यह कितना बड़ा मजाक हो रहा है? सामानों के दाम के बारे में भी नियम बना लेना चाहिए कि जितनी लागत में वह सामान तैयार होता है, चाहे वह सीमेन्ट हो, जिस तरह से सीमेन्ट के मालिकों ने सीमेन्ट का दाम एकबारगी 500 रुपये, डेढ़ सौ रुपये और दो सौ रुपये चढ़ाया, जिस तरह से दवा के व्यापारी, जितनी दवा की लागत होती है, उसके तीन सौ परसेंट या चार सौ परसेंट भाव तय करते हैं, सरकार को यह फार्मूला बना लेना

चाहिए कि कारखाने की जो चीज जितने में बनती है, उसके ex-factory price में सरकारी लगान भी शामिल हो और वह चीज लागत से ड्योढ़े या दूने से ज्यादा में न बिकने देंगे। वह चीज जितने में तैयार होती है, ड्योढ़ा या दूना, जो तय कर लीजिए, लेकिन उसे बहुत आगे मत बढ़ने दीजिए। अगर कारखाना लूटता रहेगा तो गांव का किसान तो अपने खेत से लूट नहीं सकता, लेकिन जब कभी-कभी वह सड़क पर निकलता है तो वह फावड़े से लूटने लगता है। ...**(समय की घंटी)**... सन् 1942 में और जयप्रकाश जी के आंदोलन में हम लोगों ने देखा है। सर, किसान का बेटा एक सपना लेकर निकला था, क्योंकि वह जानता था कि 1902 का कानून उसके लिए नहीं बना है, बल्कि बड़े-बड़े उत्पादक जो लंदन में बसा करते थे, उनके लिए बना है। जब वह निकल पड़ा तो अंग्रेज का सूरज डूब गया। हम हुकूमत करने वाले लोग अगर यह तसल्ली करते हैं कि किसान गुस्सा नहीं करता, श्री शिवानन्द तिवारी ने भी कहा कि कोई बगावत क्यों नहीं होती है? नायडु साहब की बात पर हमें याद आया कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हर आदमी पूछता है कि महंगाई के बारे में आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? महंगाई एक बहुत बड़ा रोग है। हमारे यहाँ यह जो काठ की लकड़ी है, इसमें घुन लग जाती है, लेकिन वह घुन दिखाई नहीं पड़ती है। एक बड़ा-सा कीड़ा होता है, जिसको "मंगरा" कहते हैं, वह पूरी लकड़ी में छेद कर देता है। महंगाई भी मंगरा-जैसा ही एक कीड़ा है। इससे बिल्डिंग तो जल्दी नहीं गिरेगी, कोई खौफनाक हालत पैदा नहीं होगी। पहले जो चार रोटी खाता था, आज वह दो रोटी ही खाकर गुजारा करता है। आज 18 रुपये, 22 रुपये किलो आलू हो गया है। अब आलू कोई नहीं खाता। एक परिवार में पांच आदमी दो आलुओं को आधा-आधा टुकड़ा करके, उसमें रसा डाल कर, खा लेते हैं। हमने उनका घर देखा है। सर, आज दाल बहुत महंगी हो गई है। हमारी बहू ने थोड़ी-सी दाल में टमाटर भी डाल दिया, उसमें प्याज भी डाल दिया और लौकी भी डाल दी। हमने पूछा कि क्या कर रही हो, यह दाल है या सब्जी? उसने कहा कि यह दाल है, बाबूजी। यह हमारे घर की हालत है! हम चाहेंगे कि इस हालत को मंत्री जी समझें। यह अकेले इनके बूते की बात नहीं है। हम जानते हैं कि इसमें उद्योग मंत्रालय भी आएगा, वित्त मंत्रालय भी आएगा, सब लोग मिलकर इसे करें। वरना, इन्होंने ऐलान किया है कि जो बहुत गरीब होंगे उनको हम 25 किलो गेहूं देंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 25 किलो गेहूं की रोटी वे खाएंगे किस चीज से? दाल तो है नहीं, सब्जी की हांडी तो बंद है, तो क्या गरीब लोग नमक के साथ खाएंगे आपका 25 किलो गेहूं? हमारी गरीबी का इतना बड़ा मजयक क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा मजयक क्यों कि आप हमको गेहूं दे दें और कहें कि जाओ बेटे खाओ और अपनी जिन्दगी बिताओ, लेकिन किसके साथ खाएं? हम आदमी हैं, गाय-बैल नहीं हैं, हमारी जुबान में बचपने से taste आ गया है, लेकिन खाएं तो किसके साथ खाएं, न दाल है न सब्जी है। इसलिए उनको दाल-सब्जी भी दीजिए और मैं चाहूंगा कि भारत सरकार को पक्के तौर पर यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हिन्दुस्तान में किसी भी आदमी को इस हालत में नहीं पहुंचने देना है कि वह आधा पेट खाए। क्योंकि, आधा पेट खाने का मतलब है कुपोषण और कुपोषण का मतलब है अपनी मौत को जल्दी न्यौता देना। तो यह जिम्मा लेना पड़ेगा, जो गरीब हैं उनके लिए भी और जो अमीर हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब्जी तो बड़ी खेल-खिलवाड़ की चीज है। मैं बाजार घूमता हूं, सर, मैं ऐसा नहीं हूं कि पार्लियामेंट में ही आऊं। तो बाजार में मैंने देखा है कि दुकान पर टमाटर जो 8 रुपए किलो होता है, जब मैं शाम को 7 बजे वही टमाटर खरीदने जाता हूं, कई कचहरी के वकील लोग भी आते हैं हमारे साथ, तो डेढ़ रुपए किलो हो जाता है। क्योंकि टमाटर बेचने वाला जानता है कि कल सड़ जाएगा। तो कुछ कच्चा माल है। खेती से जो पैदावार होती है, यह कच्चा माल है, कारखाने से जो पैदावार होती है, वह पक्का माल है। यह सीधी-सीधी लड़ाई कच्चे माल और पक्के माल के बीच में है और सरकार और उसके अफसर इससे सचेत नहीं हो सकते। ये तो वेज बोर्ड से अपनी तनखाह बढ़वा लेते हैं और हम MP लोगों को भी कुछ ज्यादा सहूलियत दे देते हैं, इधर कुछ सेलेरी वगैरह बहुत बढ़ाने के बारे में सोच लेंगे, बस हम लोग भी पगला जाएंगे। लेकिन, सच यह है कि आम आदमी

त्राहि-त्राहि कर रहा है, सरकार को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जो आम आदमी की आह निकलती है, वह रोज नहीं निकलेगी, वह अपने बाल-बच्चों को संभालता है। लेकिन, दस साल, पन्द्रह साल के बाद जब वह सड़क पर निकलता है, तो जिस किसी की सरकार हो, चाहे अंग्रेज की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो, जब आम आदमी अपनी आह बटोरकर सड़क पर निकलता है तो वह सरकार तिलमिलाकर गिर जाती है। हम नहीं चाहते कि वह नौबत आए, क्योंकि अभी हम इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं और हम यह नहीं चाहते कि इनकी सरकार गिरे। इसलिए हम सलाह दे रहे हैं कि आम आदमी के भोजन का इंतजाम कीजिए। धन्यवाद सर।

SHRI A. ELAVARASAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, thanks a lot for allowing me to speak in my mother tongue, that is, Tamil.

*Honourable Deputy Chairman Sir, Thank you very much for giving me this opportunity to participate in this short duration discussion on the price rise of essential commodities. Prices of essential commodities have been increasing continuously. During the past few months, anybody could witness the sky rocketing of prices. This shows the indifference of the Union Government in controlling the prices of essential commodities.

Honourable Deputy Chairman Sir,

A few months ago, the Union Government was asked about the reason for this price rise. Do you know what the reply of the Government is? The Government had replied that inflation had gone up to 13% and explained that prices have risen because of the rising inflation level. On 18th of July and till the end of July inflation has gone down to the level of -1.54% (minus one point five four per cent). Why prices have not gone down? When price rise is on the increasing level, the Government has explained that it is mainly because of rising level of inflation. But when inflation has gone down, why the prices of essential commodities have not been reduced? I humbly request the Honourable Minister to give the reason for this disparity.

The poorer section of people, the common man, the villagers, the people living below the poverty line (BPL) and all sorts of people are suffering because of the price rice. Prices of all essential commodities salt, tamarind, chilly, pulses, cereals, edible oils, and vegetables have increased. Buying of essential commodities have become a distant dream for the poor and downtrodden people. If the price rise continues like this, even for going to a tea shop, one has to take money in a suitcase. It will not take much time to reach such a situation.

The Union Government have listed out some reasons for price rise. Some experts also have listed the reasons. I would like to point out an instance for explaining how the prices have risen in the past few months, particularly in the few months after the 15th General election to the Lok Sabha. I have a data of market prices, with regard to pulses, sold in Virudhunagar district of Tamil Nadu. In April, the price of one quintal of pigeon pea (Tur dal) had been Rs. 5,500. Its present rate is Rs. 8,200. The price of Black gram (Urad dal) in April, had been Rs. 4,900 per

*[English translation of the original speech delivered in Tamil.]

quintal. But now, the price of black gram per quintal has gone upto to Rs. 5,700. Mr. Deputy Chairman sir, If one considers the price of Green gram (moong dal), one quintal of green gram had cost Rs. 5,200 in April. At present, its price has gone to the level of Rs. 8,800 per quintal. The price of Bengal gram has increased from Rs. 2,100 per quintal to Rs. 2,500 per quintal. Throughout India, the price of pigeon pea has increased upto the level of 35% and that of black gram has increased upto the level of 22%. This has happened within one year. These are the views of eminent economic experts.

Honourable Deputy Chairman Sir,

A statistics, issued by the Union Ministry of Food, Consumer Affairs and Public Distribution, shows the price rise of essential food materials in four metropolitan cities such as Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, in one year. In Delhi, the price of rice has gone upto 22% and in Mumbai upto 13%. There is no change in the price of rice in Kolkatta, but in Chennai, the price of rice has gone upto 13%. With respect to Sugar, the prices have gone upto 47% in Delhi, 43% in Mumbai, 29% in Kolkata and 42% in Chennai. Throughout India, Onion occupies an important place in the preparation of staple food items of poorer sections. What is the per cent age increase in the price of onions? According to the statistics furnished by the Union Ministry, in Kolkata and in Chennai, the price of Onion has been doubled, *i.e.* there has been 100% increase in the price of onions. But the situation is worse in Delhi and Mumbai. In Delhi, the price of onion has gone upto 111% and in Mumbai, it has gone upto 128%.

At this juncture, I would like to point out the important reasons for this price rise, to the Hon'ble Prime Minister of India and to the Hon'ble Minister for Food, Consumer Affairs and Public Distribution. First and foremost reason for this price rise, is the Union Government; Second is the inflation. Third reason is black marketeering, and Fourth reason is hoarding of food materials. A large amount of food material is hoarded by black marketer resulting in price rice of essential commodities in open market. As a result, the common man could not afford to it. Fifth reason is the petrol, diesel price hike. Sixth reason is online trading. And seventh reason is the failure of monsoon and the changing climate. All these reasons have to be eliminated and should be rectified by the Government to enable the common man to purchase essential commodities at affordable prices. I humbly request the Hon'ble Minister that the Government has to take serious efforts to supply essential commodities at reasonable prices.

Honourable Deputy Chairman Sir,

Please give me two more minutes. This is a very important issue.

If you strike the bell at this point of time, it is equivalent to striking the hearts of crores of people. I do not desire to give such an embarrassing situation to you. Therefore, I humbly request you to give some more minutes to this young man who desires to address the grievances of the poor people.

I told that the Union Government is responsible for this price rise. I would like to point out the reason for criticizing the Union Government. Some months ago, a Central Government organization called The India Meteorological Division had issued a statement. Accordingly, pigeon pea had not been cultivated at 4 lakh acre of land this year to failure of monsoon and therefore scarcity for pulses may rise this year unlike last year. Next day, the price of pigeon pea had gone upto Rs.2,000 per quintal. But at the end of July, the same India Meteorological Division reversed its statement and apologized that they had issued a wrong statement. They said that pigeon pea had been cultivated in 4 lakh acre of land as is being done every year. After this reversal of announcement, the price of pigeon pea has been reduced to Rs.700 per quintal. What is the reason for this contradiction? I would like to point my fingers at the Union Government only.

In addition to all of the above reasons pointed out by me, the most important reasons for this price rise is the wrong economic policy of the then finance minister of the UPA-I government who had been in the finance ministry for four years. Only the mother knows the labouring pain while giving birth to a child. Similar is the plight of common man, who suffers from the price rise of essential commodities. If the Government want to protect the common man, it had to reduce the prices of essential commodities. Only the common man feels the pain of the price rise of essential commodities. Therefore, the Government had to address their grievances by reducing the price of essential commodities. With these words, I conclude my speech. I once again thank you very much for giving me this opportunity. Thank you.

SHRI K.E. ISMAIL (Kerala): *Thank you Mr. Deputy Chairman Sir, I will speak in Malayalam. The unprecedented rise in the prices of foodgrains and other essential commodities is the burning issue that agitates the minds of everyone in this country. I am not going to quote any figures to show how the prices of every consumer items have gone up. The Hon'ble Member from Tamil Nadu who spoke before me has explained how the prices of rice, cereals and other items have increased by citing actual figures. Other Hon'ble Members have also spoken extensively on the subject.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN IN) THE CHAIR]

Mr. Vice-chairman, sir, since I am speaking in Malayalam, I expect a generous attitude towards me, sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I can understand your speech without the help of translation.

SHRI K.E. ISMAIL: Sir, the price rise affects Kerala most severely. Because Kerala has to depend on other states for all commodities the effect of the price rise is felt the most in Kerala. Therefore immediate steps should be taken by the Government to check the escalation of prices of essential commodities. It is this Government that has admitted that the majority of the

---

*[English translation of the original speech delivered in Tamil.]

population of our country live below the poverty line. It has been admitted by the Government that 77% of our population live in a condition where getting at least a single meal a day is difficult. The burden of price rise is thrust on the shoulders of this deprived section of the society. Those who are already living in a state of abject poverty are pushed further into deeper miseries.

Sir, crores and crores of people who bear the brunt of the price rise and thus driven to extreme life situations fall easy prey in the hands of fundamentalist and separatist forces. They are being targeted, to be recruited into their fold, by religious fundamentalists, terrorist forces and divisive agencies. These elements are trying to use the members of this vast deprived class as pawns in their games. Therefore, sir, in order to prevent the growth of separatism, terrorism and religious fundamentalism we need to address ourselves to the miserable plight of the millions of people of our country and find a solution to mitigate their sufferings. So steps should be taken to find a solution to the problems faced by a vast section of our population.

Sir, the rise in the prices of food items and other essential commodities that we witness now has been triggered by the hike in the prices of petrol, diesel and other petroleum products. Who get benefited from this hike other than the owners of big oil companies? This merely adds to the misery of the common man. So, the one necessary step to bring some solace to the suffering masses of our country is to reduce the prices of petroleum products. I urge upon the Government to take initiative in this direction immediately.

Sir, the trade and business of our country are controlled by people who indulge in speculative trade, hoarding and black marketing. This Government should show the willingness to initiate bold actions against black marketers and those who indulge in speculative trade and hoarding. There is no other solution to the present crisis.

Sir, Kerala is a state where Public Distribution System has been functioning quite smoothly and effectively for many years. Statutory rationing system is in place in Kerala since 1966. Sir, I think the Hon'ble Minister and others are under the impression that they are doling out some favour by giving some amount of rice to Kerala. Is it a right attitude, Sir? It was agreed in 1966 that Kerala will be provided sufficient food grains. It was on the basis of certain fundamental factors that an understanding to this effect was reached upon between the State Government and the Central Government. Kerala is the biggest contributor of valuable foreign exchange to the country. Be it rubber, or coffee, or cardamom or marine products or spices, through the export of its produces, Kerala is earning the country huge sums of foreign exchange. So in order to protect and promote exports an understanding was reached upon to the effect that Kerala will be provided with sufficient supply of food grains. It is highly unfortunate that the people of that state are divided into two categories, namely APL and BPL, and thereby depriving around 60 lakhs of people of their right to get food grains through PDS. I would say that it was indeed a cruel decision. Only 10 lakh people are now eligible to get rice at the BPL rate. It is

denied to the remaining 60 lakhs ration card holders. It is the State government that is providing rice to this large section of ration card holders in spite of the acute financial crunch. So, I request the Hon'ble Minister to do away with the APL, BPL distinction. It should be ensured that the ordinary people of our land get foodgrains at a fair and reasonable rate. The Public Distribution system should be strengthened so that the people of our country get food items and other essential commodities at affordable rates.

Sir, the Hon'ble Chief Minister of Kerala and the Minister of Civil Supplies met the Hon'ble Minister of Agriculture yesterday. I am glad that the Hon'ble Minister made a promise to them that 50 thousand tonnes of rice would be given to the State during Onam festival season. But Sir, I have a request in this connection. This 50 thousand tonnes of rice should be made available at the BPL rate. It does not really do any good if the rice is provided at the market price. So sufficient quantum of rice should be made available to the State.

Sir, the ordinary people of our country are gradually being driven into miserable conditions. There should be concrete action to ameliorate the hard living conditions of the people. If the Government does not come forward to intervene in an effective way our country may be relegated to the league of poor nations which are ill famous for deaths due to poverty. We cannot allow our country to fall into that state of ignominy. The country is important. The people are important. It is the duty of the Government to curb black market, speculative trade and hoarding and save the millions of our country men from poverty. The basic reasons behind the price rise should be identified and tackled effectively. Such actions are the need of the hour.

Kerala is currently facing a serious financial crisis. So the Central Government should come forward to ensure timely supply of sufficient amount of rice to Kerala. There was even an unfortunate situation when the Central Government had decided to curtail the quota of rice to the state. The quantum of rice promised for Onam should be increased from 50 thousand tones. I request the Hon'ble Minister, through you Sir, to provide sufficient quantum of rice to Kerala in order to enable the State to continue giving rice at Rs. 2 per Kilogram. Immediate steps should be taken to ensure that the millions of poor people in our country get their food grains at an affordable rate. With these words I conclude.

THE VICE CHAIRMAN (PROF P.J. KURIEN): It is interesting to hear Malayalam in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is interesting to hear Malayalam in the House. Now, Shri M. V. Mysura Reddy.

SHRI D. RAJA: Sir, he must speak in Telugu. *...(Interruptions)...*

SOME HON. MEMBERS: Sir, let him speak in Telugu. *...(Interruptions)...*

SHRI M. V. MYSURA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I did not give notice. At the outset... *...(Interruptions)...* I didn't give notice; how can I speak in Telugu?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There was no intimation. He did not give intimation in advance and so, it is not possible. You may speak in English. *...(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, you said that since there was no prior intimation, Telugu interpretation is not available. I would like to know whether we have a Telugu interpreter.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, we have.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Okay, it is available. But then, in how many languages is interpretation not available? *...(Interruptions)...* It is not only about South India; there are other languages as well — Punjabi, Kannada, Ahomia, Bengali, Oriya, and so on. Oriya is there. Are all language interpreters available in the Rajya Sabha Secretariat? That is my point. If they are not available, please see to it. We can have more speakers like this who can speak in their mother tongue and can articulate more efficiently and frankly. Secondly, Sir, after the first round is over, please adjourn the House.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): After this, there are Special Mentions. Then I will adjourn the House.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, I am referring to the answer of Unstarred Question No.3414. The reply came on today. I quote, 'The Government monitors the price situation regularly with the price stability being high on its agenda. Measures taken to contain the prices of essential commodities include selective ban on imports, future trading in foodgrains, Zero Import Duty on selective food items, permitting imports of pulses and sugar by public sector undertakings, distribution of imported pulses and edible oils through PDS and release of higher quota of non-levy sugar. In addition to this, the State Governments have been empowered to act against the hoarders of food items by keeping them in abeyance, with removal of restriction on licensing, stock limits and movement of food articles under the Essential Commodities Act, 1955.' The same stark reply is there for Calling Attention, Short Duration Discussion or maybe in reply to the debate. Sir, due to lopsidedness and adhocism in implementing these policy measures, it neither protects the interests of farmers, nor does that help consumers. In reality, prices are still rising. Sir, the production of rice is in comfortable position, but still the price of rice is increasing. Sir, I will remind the Minister of his statement at FICCI Conference in 2007. I quote, 'If any Government wants to implement the scheme of PDS, it should provide money from the State revenue to purchase foodgrains from the open market.' Sir, as per the buffer norms of FCI in 2005, the buffer stock should be 120 lakh tonnes as on April, but rice buffer stock should be more than 2 lakh tonnes. In 2005-06, Andhra Pradesh contributed 49 lakh tonnes, in 2006-07 it went up to 53 lakh tonnes and in 2007-08 it suddenly zoomed up to 75 lakh tonnes. With this additional 75 lakh tonnes, 60 lakh tonnes of rice, which is more than the buffer-stock norms, is left in the open market. He preached one thing and practised another thing. This led to the smuggling of rice to the extent of 30 to 35 lakh tonnes by rice-millers to other States or to

other countries. Everybody knows that from Kakinada port, it is smuggled out to other countries in the code name of *mallapoovu*. Probably, the Minister knows about this scam. It also occurred during 2007 when here also, in Delhi, rice-millers exported rice to Sierra Leone and other African countries, probably as a part and parcel of the scam that took place in Andhra Pradesh.

Then, there is one more point. The Ministry had prohibited the export of non-basmati rice on 15th October, 2007. Then, again, in November, 2008, also, export of non-basmati rice was prohibited. But, strangely, two rice millers got permission on 18th November, 2008, for export of 25 tonnes of non-basmati rice, namely, Venkata Chalapati Modern Rice Mill, Puducherry; and Bharat Exporters of Ranga Reddy District of Hyderabad in Andhra Pradesh. Even though there was a shortage of rice in Andhra Pradesh in 2008, they got this permission. I can understand that the Government can change the policy. But, individual exemption to rice millers for export would result in shortage in the open market for rice and they will resort to smuggling, hoarding, and all those things, and the price rise will be there. *...(Time-bellrings)...* I will complete within two minutes.

Regarding pulses, I would like to say that traditionally, they were called poor man's protein. But, it became a rich man's in recent years. The price rise is as follows: (i) *Chana,* in 2004, was at Rs. 1350; in 2009, during the same period, it was Rs. 2350, (ii) *toor* dal was at Rs. 1780, and it is now Rs. 5500, (iii) *urad dal* was at Rs. 1400 in 2004, and now it is Rs. 4400 in 2009, (iv) *moong dal* also was at Rs. 1600, and now it is Rs. 4200. The prices have risen by 65 to 215 per cent in the last five years. In retail market, the prices of *toor*, *moong* and *urad* really touched, in some places, the mark of Rs. 90, Rs. 99 and Rs. 100. In terms of cricket connection of present Food Minister, it is nearing century, or might have crossed century. If this Government continues for the next five years, it may even hit a double century also. That is the situation because on the one hand, the Government is importing pulses for domestic requirement, and on the other hand, roughly, 60 thousand tonnes of these pulses were stored in Tuticorin, Kolkata and Visakhapatnam ports. This scam was also telecast by television channels and published by newspapers. On the one side, there is deficiency, and on the other, the Government itself is hoarding pulses as stocks. These short-term measures will not control the prices. The Government has to wake up and take appropriate measures to increase the production of pulses also. Wherever there is deficiency, they have to concentrate on measures to increase the production of essential commodities.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The Short Duration Discussion on the situation arising out of continued rise in prices of essential commodities in the country has not concluded yet. It will continue on Thursday, 6th August, 2009.